

याचिकाकर्ता

प्रकाश चंद्र अग्रवाल

बनाम

प्रतिवादी:

बिहार राज्य एवं अन्य

निर्णय की तारीख 26/08/1985

बेंच:

वेंकटरमैया, ई. एस. (न्यायमूर्ति)

पीठ:

वेंकटरमैया, ई. एस. (न्यायमूर्ति)

मिश्रा, आर. बी. (न्यायमूर्ति)

उद्धरण:

1985 ए. आई. आर. 1709

1985 एस. सी. आर. पूरक। (2) 693

1985 एस. सी. सी. (4) 105

1985 स्केल (2) 377

अधिनियम

बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) भर्ती नियम, 1955, नियम 15 और 19-राज्य सेवा आयोग द्वारा चयन उच्च न्यायालय के परामर्श से साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए योग्यता अंक 40 प्रतिशत निर्धारित किए गए-बाद में आयोग ने उच्च न्यायालय के

परामर्श से 38 प्रतिशत अंक फिर से निर्धारित किए-38.8% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है लेकिन नियुक्त नहीं किया जाता है क्या वह उचित है।

हेडनोट:

बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (भर्ती) नियम, 1955 नियम 15 के खंड (ए) द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को बिहार न्यायिक सेवा में मुन्सिफ के पदों के लिए लिखित परीक्षा में किसी भी या सभी विषयों में योग्यता अंक निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। 80 करने से पहले आयोग को उच्च न्यायालय से परामर्श करना पड़ता है। नियमों के नियम 17 में प्रावधान है कि यदि किसी उम्मीदवार ने नियम 15 के तहत निर्धारित योग्यता अंकों से कम अंक प्राप्त किए हैं तो वह वाइवा वॉस टेस्ट के लिए पात्र नहीं होगा, जबकि नियम 19 के तहत वाइवा वॉस टेस्ट में प्राप्त अंकों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ा जाना है।

अपीलार्थी 19 वीं प्रतिस्पर्धात्मक न्यायिक सेवा परीक्षा में उपस्थित हुआ और मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों सहित सभी 416 अंक प्राप्त किए। हालांकि, उन्होंने लिखित परीक्षा में केवल 38.8 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। सबसे पहले 83 उम्मीदवारों को मुन्सिफ के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में, आयोग ने मुन्सिफ के रूप में नियुक्त होने के लिए सरकार को 38 उम्मीदवारों की एक और सूची प्रस्तुत की, लेकिन इसमें अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं किया गया, भले ही उसमें क्रम संख्या 36,37 और 38 में उन उम्मीदवारों के नाम शामिल किए थे जिन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से कम अंक प्राप्त किए थे। सफल उम्मीदवारों की सूची में अपना नाम शामिल नहीं किए जाने से व्यथित होकर उन्होंने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया।

अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपनी अपील में तर्क दिया कि आयोग ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए योग्यता अंकों के रूप में लिखित पत्रों में 38 प्रतिशत अंक निर्धारित किए हैं।

इसलिए, उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद नियम 15 (ए) के तहत और नियम 19 के तहत तैयार किए गए सफल उम्मीदवारों की सूची से उनका नाम हटाना नियमों के विपरीत था। हालाँकि, प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी का नाम नियम 19 के तहत तैयार की गई सफल उम्मीदवारों की सूची में इस आधार पर शामिल नहीं किया गया था कि उसने लिखित पत्रों में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए थे जो नियम 15 (ए) के तहत निर्धारित योग्यता अंक थे।

अपील की अनुमति देते हुए,

अभिनिर्धारित: 1. उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया पूरा दृष्टिकोण गलत है। उच्च न्यायालय को पहले इस प्रश्न पर निर्णय लेना चाहिए था कि क्या आयोग ने योग्यता अंकों के रूप में 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किए थे या 38 प्रतिशत जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है और फिर उसे यह तय करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए था कि क्या अपीलार्थी का नाम नियमों के नियम 19 के तहत तैयार किए गए दायित्व से ठीक से बाहर रखा गया है या नहीं। यह कहना गलत था कि आयोग ने योग्यता अंक 40 प्रतिशत पर केवल इसलिए निर्धारित किए क्योंकि उसने नियम 19 के तहत तैयार की गई सूची में 40 प्रतिशत से कम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले किसी भी उम्मीदवार के नाम शामिल नहीं किए थे। इस तरह का गैर-समावेशन अपने आप में और अधिक के बिना आयोग द्वारा किए गए निर्णय के बराबर नहीं है। आयोग ने वास्तव में यह दलील नहीं दी कि उसने ऐसा कोई नया निर्णय नहीं लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा आयोग की कार्रवाई का समर्थन करने के लिए यह एक नया मामला है, जो योग्यता अंक 38 प्रतिशत

तय करने के अपने फैसले के विपरीत है। यह हो सकता है कि वास्तव में, 83 उम्मीदवारों के पहले बैच में अनारक्षित श्रेणी से संबंधित कोई भी उम्मीदवार लिखित पत्रों में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किया हो, लेकिन प्रासंगिक वह मानक है जो उक्त सूची तैयार करने के समय लागू किया गया था। यह सूची आयोग द्वारा अनारक्षित श्रेणी के लिए 38 प्रतिशत निर्धारित योग्यता अंकों के आलोक में बिना किसी संदेह के तैयार की गई होगी, जिसके आधार पर अपीलार्थी सहित दोनों बैचों से संबंधित सभी उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी। जब अगली सूची तैयार की गई तो उस मानक को बदला नहीं जा सका। उच्च न्यायालय इस मामले के इस पहलू की सराहना करने में विफल रहा है।

2. आयोग ने अनारक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए नियमों के नियम 15 (ए) के तहत योग्यता अंकों के रूप में 38 प्रतिशत निर्धारित किए थे। योग्यता अंकों के रूप में 38 प्रतिशत निर्धारित करने के बाद, आयोग के लिए लिखित परीक्षा में 38.8 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के नाम को केवल इसलिए बाहर करना संभव नहीं था क्योंकि उच्च न्यायालय ने पहले ऐसा किया था आयोग द्वारा परामर्श किए जाने पर यह सिफारिश की गई कि 40 प्रतिशत अंक योग्यता अंक होने चाहिए। जब तक नया निर्धारण किया जाता है, लिखित परीक्षा में 38 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाला प्रत्येक उम्मीदवार मौखिक परीक्षा में उपस्थित होने और लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता के क्रम में नियमों के नियम 19 के तहत तैयार की गई सूची में शामिल होने का हकदार होगा।

तत्काल मामले में, स्वीकार किया जाता है कि जिन दो उम्मीदवारों के नाम क्रम संख्या 36 और 37 के खिलाफ दिखाए गए हैं, उन्होंने कुल 415 अंक प्राप्त किए थे और क्रम संख्या 38 के खिलाफ दिखाए गए उम्मीदवार ने 413 अंक प्राप्त किए थे, जबकि अपीलार्थी ने 416 अंक प्राप्त किए थे। इसलिए, अपीलार्थी का नाम आयोग द्वारा नियम 19

के तहत सरकार को सौंपी गई सूची में शामिल किया जाना चाहिए था, जिसे क्रमांक संख्या 36 पर उम्मीदवार के नाम के ऊपर रखा जाना चाहिए था। 80 नहीं करके आयोग ने नियमों और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का भी उल्लंघन किया था। इसलिए, निर्णय को सरकार को एक संशोधित सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है जिसमें क्रमांक संख्या 36 के ऊपर अपीलार्थी का नाम दिखाया गया है और राज्य सरकार को नियमों के नियम 21 के तहत मुन्सिफ के रूप में नियुक्ति के लिए अपीलार्थी के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है जैसे कि उसका नाम उस उम्मीदवार के ऊपर दिखाया गया था जिसका नाम क्रमांक संख्या 36 के सामने दिखाया गया है। आगे यह आदेश दिया जाता है कि उसकी नियुक्ति पर, अपीलार्थी को वरिष्ठता सूची में क्रमांक संख्या 36 के सामने दिखाए गए उम्मीदवार के ऊपर रखा जाएगा और उसे सभी वेतन वृद्धि आदि दिए जाएंगे जैसे कि उसे उस तारीख को नियुक्त किया गया था जिस दिन क्रमांक संख्या 36 में उम्मीदवार की नियुक्ति की गई थी।

निर्णय

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1985 की सिविल अपील सं. 4011

1984 के सी.डब्ल्यू. जे.सी. सं. 1449 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांकित 16.4.1985 के निर्णय और आदेश से।

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से।

प्रतिवादी की ओर से जया नारायण और यू. एस. प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय वेंकटरमैया, न्यायमूर्ति, द्वारा दिया गया।

यह 16 अप्रैल, 1985 के 1984 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1449 में पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति द्वारा एक अपील है,

जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयोग (इसके बाद 'आयोग' के रूप में संदर्भित) द्वारा दिसंबर 1979 में आयोजित 19 वीं प्रतिस्पर्धी न्यायिक सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मामले के तथ्य संक्षेप में ये हैं। आयोग द्वारा अक्टूबर, 1979 के महीने में जारी एक विज्ञापन के अनुसार, जिसमें बिहार न्यायिक सेवा में मुन्सिफ के पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, अपीलार्थी ने समय के भीतर आयोग के समक्ष अपना आवेदन दायर किया। वे दिसंबर, 1979 के महीने में आयोजित प्रतिस्पर्धात्मक न्यायिक परीक्षा में उपस्थित हुए, जिसमें उन्हें आवंटित अनुक्रमांक 388 था। इसके बाद 27 जुलाई, 1981 को वे आयोग द्वारा आयोजित वाइवा वॉस टेस्ट में उपस्थित हुए। अपीलार्थी ने मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों सहित सभी 416 अंक प्राप्त किए। हालाँकि, उन्हें नियुक्ति का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ, हालाँकि एक उम्मीदवार जिसने कुल मिलाकर उससे कम अंक प्राप्त किए थे, उन्हें मुन्सिफ के रूप में नियुक्त किया गया था। सफल उम्मीदवारों की सूची में अपना नाम शामिल न किए जाने से व्यथित होकर उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय में उपरोक्त रिट याचिका दायर की, जिसे अंततः ऊपर बताए गए अनुसार खारिज कर दिया गया। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की जाती है।

सबसे पहले सरकार ने 83 उम्मीदवारों को मुन्सिफ के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया था। बाद में यह सभी 139 उम्मीदवारों को मुन्सिफ के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। आयोग द्वारा सफल उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत किए जाने के बाद, सरकार ने 16 सितंबर, 1982 को 83 उम्मीदवारों को मुन्सिफ के रूप में नियुक्त किया। बाद में 3 मई, 1983 के अपने आदेश द्वारा, 14 और उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया जो 'सबसे पिछड़े वर्गों' से संबंधित थे। इन 14 नियुक्तियों को कुछ उम्मीदवारों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर दो रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी, अर्थात्, सी.डब्ल्यू.जे.सी.

1868/1983 और सी.डब्लू.जे.सी.2209/1983। उच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया, आरक्षण के आधार पर उक्त 14 उम्मीदवारों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया और आयोग को नियमों के अनुसार सफल उम्मीदवारों के नाम आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके बाद आयोग द्वारा 18 उम्मीदवारों के नामों वाली एक और सूची प्रस्तुत की गई। उच्च न्यायालय के समक्ष 1983 के एम. जे. सी. संख्या 600 में अवमानना याचिका दायर किए जाने के बाद, 20 उम्मीदवारों के नामों वाली एक और सूची प्रस्तुत की गई थी। इन 38 उम्मीदवारों की समेकित सूची में आयोग ने अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं किया, भले ही उसने क्रम संख्या 36,37 और 38 में उन उम्मीदवारों के नाम शामिल किए थे जिन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से कम अंक प्राप्त किए थे। इस अपील में हमें यह जांचने के लिए कहा गया है कि क्या उस सूची से अपीलार्थी का नाम निकालना उचित था या नहीं। बिहार सिविल सेवा की न्यायिक शाखा में भर्ती बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (भर्ती) नियम, 1955 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) द्वारा विनियमित की जाती है, जिसे बिहार के राज्यपाल ने पटना में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार और आयोग के परामर्श के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 के तहत घोषित किया है। नियमों का नियम 2 (ए) में यह प्रावधान है कि मुन्सिफ के पदों पर भर्ती नियमों के अनुसार की जाएगी। नियमों के नियम 3 में राज्यपाल को प्रत्येक वर्ष यह तय करने की आवश्यकता होती है कि मुन्सिफ के संवर्ग में रिक्तियों की संख्या को मूल आधार पर या अस्थायी आधार पर या दोनों आधार पर नियुक्तियों द्वारा दाखिल किया जाए। इस तरह का निर्धारण किए जाने पर आयोग को नियमों के नियम 4 के अनुसार प्रत्येक वर्ष में इस तरह से घोषणा करने की आवश्यकता होती है, जैसा कि वह सोचता है, एक प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों पर सीधी भर्ती द्वारा उस वर्ष भरे जाने वाले रिक्तियों की संख्या। आयोग को नियमों के अनुसार मुन्सिफ के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जानी आवश्यक है। योग्यताएँ जो एक मुन्सिफ

के पद के लिए उम्मीदवार को नियमों के नियम 6 में निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा नियमों के परिशिष्ट 'सी' में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित की जानी है। नियमों के परिशिष्ट 'सी' का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

विषय	अंक
1. अनिवार्य -	
(1) सामान्य ज्ञान (सामयिकी सहित)	150
(2) प्राथमिक सामान्य विज्ञान	100
(3) सामान्य हिंदी	100

यह अनिवार्य पत्र एक योग्यता विषय होगा जिसमें सभी उम्मीदवारों को न्यूनतम 30 अंक लाना होगा। लेकिन इस पत्र में प्राप्त अंकों को योग्यता के निर्धारण के उद्देश्य से नहीं जोड़ा जाएगा।

2. ऐच्छिक। - उम्मीदवारों को विषय संख्या 4 में उपस्थित होना चाहिए और शेष पांच में से किसी भी तीन का चयन करना चाहिए।

विषय -	
(4) साक्ष्य और प्रक्रिया का कानून	150
(5) भारत और इंग्लैंड का संवैधानिक कानून	150
(6) हिंदू कानून और मुसलमान कानून	150
(7) संपत्ति के हस्तांतरण का कानून	

और कानून सहित समानता के सिद्धांत

न्यास और विशिष्ट राहत। 150

(8) अनुबंध और टोर्ट्स का कानून 150

(9) वाणिज्यिक कानून 150

3. वाइवा वॉस टेस्ट 200

नियम का नियम 15 जो इस मामले के उद्देश्य के लिए 18 सामग्री निम्नानुसार है:

"15 (क) आयोग के पास पाटन उच्च न्यायालय के परामर्श से लिखित परीक्षा में किसी भी या सभी विषयों में योग्यता अंक तय करने का विवेकाधिकार होगा।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जब तक कि अन्य उम्मीदवारों के लिए लागू मानकों के अनुसार लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की संख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक उम्मीदवारों की संख्या से काफी अधिक न हो;

बशर्ते कि नियुक्ति के लिए किसी विशेष उम्मीदवार की उपयुक्तता निर्धारित करने में, कुल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखा जाएगा न कि किसी विशेष विषय या विषय में प्राप्त अंकों को।

(ग) वाइवा वॉस टेस्ट के लिए कोई योग्यता नहीं होंगे

नियमों के नियम 15 के खंड (ए) में आयोग को लिखित परीक्षा में किसी या सभी विषयों में अर्हक अंक तय करने की शक्ति निहित है, लेकिन इस संबंध में अपने विवेक का प्रयोग

करने से पहले आयोग को पटना उच्च न्यायालय से परामर्श करना होगा। इस मामले में नियम 15 के खंड (बी) से संबंध नहीं है। नियम 15 के खंड (सी) में प्रावधान है कि मौखिक परीक्षा के लिए कोई अर्हक अंक नहीं होंगे। नियमों के नियम 17 इस प्रकार है:

"17.लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, आयोग नियम 15 के अनुसार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के मौखिक परीक्षण की व्यवस्था करेगा:

बशर्ते कि असाधारण परिस्थितियों में और सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, आयोग, अपने विवेकाधिकार पर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा में प्रवेश दे सकता है, भले ही उन्होंने लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं किए हों।

नियमों के नियम 17 से यह स्पष्ट है कि यदि किसी उम्मीदवार ने नियम 15 के तहत योग्यता अंकों के रूप में निर्धारित अंकों से कम अंक प्राप्त किए हैं तो वह मौखिक परीक्षा के लिए पात्र नहीं होगा। नियमों के नियम 19 आयोग द्वारा राज्यपाल को सौंपी जाने वाली सफल उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बताता है। इसमें इस प्रकार लिखा है 19 मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंक लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जाएंगे। यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के अंकों में बराबर है कुल अंकों में, क्रम लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यदि संबंधित उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक भी समान है, तो बैकल्पिक पत्रों में प्राप्त अंकों की कुल संख्या के अनुसार क्रम तैयार किया जाएगा। व्यवस्थित उम्मीदवारों की सूची में से 80 आयोग उम्मीदवारों की ऐसी संख्या नामित करेगा जो सूची में उनकी स्थिति के क्रम में

राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाए। इस प्रकार किए गए नामांकन प्रत्येक वर्ष ऐसी तिथि तक राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे जो राज्यपाल निर्धारित करे।

तत्काल मामले में यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी ने लिखित परीक्षा में 38.8 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे और वह आयोग द्वारा आयोजित मौखिक परीक्षा में भी उपस्थित हुआ था। कहा जाता है कि तैयार की गई सफल उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं था। नियमों के नियम 19 के तहत इस आधार पर कि उन्होंने लिखित पत्रों में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए थे, जो उच्च न्यायालय के अनुसार नियम 15 (ए) के तहत निर्धारित योग्यता अंक थे। हालाँकि, अपीलार्थी का मामला यह है कि आयोग ने अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद नियम 15 (ए) के तहत योग्यता अंकों के रूप में लिखित पत्रों में 38 प्रतिशत अंक निर्धारित किए थे और नियम 19 के तहत तैयार किए गए सफल उम्मीदवारों की सूची से उनका नाम बाहर करना नियमों के विपरीत था। अतः इस मामले में निर्णय इस प्रश्न के उत्तर को सक्रिय करता है कि क्या आयोग ने नियमों के नियम 15 (ए) के तहत 40 प्रतिशत को लघु = योग्यता अंक के रूप में निर्धारित किया था या 38 प्रतिशत जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है। उच्च न्यायालय के समक्ष आयोग के कार्यालय में एक सहायक नीलमणि प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा दायर जवाबी-हलफनामे के पैराग्राफ 5,6 और 8 में निम्नानुसार कहा गया है:

"5. कि बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (भर्ती) नियम 15 (ए) में प्रावधान है कि आयोग को पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से लिखित परीक्षा में किसी भी या सभी विषयों में योग्यता अंक तय करने का विवेकाधिकार होगा।

6. उपरोक्त नियम को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 19वीं न्यायिक सेवा परीक्षा, पटना की लिखित परीक्षा के लिए योग्यता अंक तय करने के लिए माननीय पटना उच्च न्यायालय से परामर्श किया, उनके पत्र संख्या 14265 दिनांक 8 अक्टूबर 80 में

अन्य बातों के अलावा कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए मौखिक परीक्षा के लिए योग्यता अंक 30 प्रतिशत और शेष 40 प्रतिशत होने चाहिए। उच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के लिए विभिन्न श्रेणियों को भी स्वीकार नहीं किया।

.....

8. चूंकि सरकार ने पिछड़े वर्गों की विभिन्न श्रेणियों सहित पहले श्रेणीवार निर्धारित रिक्तियों की संख्या में संशोधन नहीं किया था, इसलिए आयोग को अंततः कानून के अनुसार उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने के लिए लिखित परीक्षा में योग्यता अंकों के रूप में निम्नलिखित निर्धारित करने पड़े।

आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता अंकों को निम्नानुसार दर्शाया गया है:

अनारक्षित	38 प्रतिशत
प्रतिशत पिछड़ा वर्ग	38 प्रतिशत
प्रतिशत सबसे पिछड़ा वर्ग	25 प्रतिशत
प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर (महिला)	25 प्रतिशत
आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग	25 प्रतिशत
(गैर-अनुसूचित जाति/गैर-अनुसूचित जाति/ गैर-एम. बी. सी.)	
एस. टी. 25 प्रतिशत	
एस. सी. 25 प्रतिशत	

आयोग की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के उपरोक्त अंश से यह देखा जाता है कि उच्च न्यायालय ने इसमें कोई संदेह नहीं था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए योग्यता अंक 40 प्रतिशत होने चाहिए जब आयोग द्वारा नियमों के अनुसार परामर्श किया गया था, लेकिन आयोग ने अंततः उच्च न्यायालय की राय पर विचार करने के बाद अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए योग्यता अंक 38 प्रतिशत निर्धारित किए थे। हम पैराग्राफ 8 में निर्दिष्ट अन्य वर्गीकरणों से संबंधित उम्मीदवारों के मामलों के साथ इस अपील में चिंतित नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी को पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के रूप में माना गया था, लेकिन इस तरह के वर्गीकरण को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में से एक में समर्थन नहीं मिला। लेकिन लिखित पत्रों में 38.8 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में मौखिक परीक्षा में बैठने के लिए पात्र था क्योंकि उसने उस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित योग्यता अंकों को पूरा किया था। आयोग ने उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद योग्यता अंकों के रूप में 38 प्रतिशत अंक निर्धारित करने के बाद आयोग के लिए उस निर्णय का पालन करने से इनकार करने और उम्मीदवारों की सूची में अपीलार्थी का नाम शामिल करने से इनकार करने की अनुमति नहीं थी, जिसे उसने नियम 19 के तहत सरकार को भेजा था। अपने निर्णय के दौरान अपीलार्थी के उपरोक्त विवाद पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

"याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि नियम 15 में होने वाली अभिव्यक्ति 'परामर्श' का अर्थ सहमति नहीं है। दूसरे शब्दों में, आयोग लिखित परीक्षा में योग्यता अंकों के निर्धारण के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह से बाध्य नहीं है। इस तर्क के समर्थन में विद्वान वकील ने उच्चतम न्यायालय के

विभिन्न मामलों का उल्लेख करने का इरादा किया जहां "परामर्श" अभिव्यक्ति की जांच की गई है।

मेरी राय में, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में नियम 15 के दायरे की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या आयोग को लिखित परीक्षा में योग्यता अंक निर्धारित करते समय उच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार निर्धारित करना है। यह सवाल उठ सकता था अगर आयोग उच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार नहीं करता। तत्काल मामले में आयोग ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य किया है। केवल इसलिए कि 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, मेरे विचार में, यह उन्हें नियुक्ति के लिए चुने जाने के किसी भी अधिकार से वंचित नहीं करेगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जवाबी हलफनामे में यह समझाया गया है कि उस समय आयोग ने 38 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को भी साक्षात्कार के लिए बुलाने का फैसला क्यों किया था। लेकिन नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करते समय, सफल उम्मीदवारों की एक सूची नियमों के नियम 19 और 20 के अनुसार सख्ती से तैयार की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को यह स्वीकार करना पड़ा कि आयोग द्वारा नियुक्त किए जाने के लिए किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं की गई है जिसने लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हों। मामले के उस दृष्टिकोण में इस समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है कि याचिकाकर्ता के साथ किसी भी तरह का भेदभाव किया गया है।

उच्च न्यायालय ने बड़े सम्मान के साथ उस प्रश्न से बचने की कोशिश की है जो उसके सामने स्पष्ट रूप से उठा था। उच्च न्यायालय ने कहा है कि तथ्यों और वर्तमान मामले की परिस्थितियों पर नियमों के नियम 15 के दायरे की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि क्या आयोग ने लिखित परीक्षा में योग्यता अंक निर्धारित करते समय उच्च न्यायालय

की सलाह के अनुसार कार्य करना और यह कि यदि आयोग ने उच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार कार्य नहीं किया होता तो उक्त प्रश्न उत्पन्न होता। उच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि केवल इसलिए कि आयोग ने उन उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया था जिन्होंने 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए थे, अपीलार्थी नियुक्ति के लिए चुने जाने के किसी भी अधिकार का दावा करने का हकदार नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने आयोग की कार्रवाई को यह कहते हुए बरकरार रखा कि चूंकि आयोग ने लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं की थी, इसलिए इस तर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी कि अपीलार्थी के साथ भेदभाव किया गया था। बड़े सम्मान के साथ, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया पूरा दृष्टिकोण गलत है। न्यायालय को पहले इस प्रश्न पर निर्णय लेना चाहिए था कि क्या आयोग ने योग्यता अंकों के रूप में 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किए थे या 38 प्रतिशत जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है और फिर उसे यह तय करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि क्या अपीलार्थी का नाम नियम 19 के तहत तैयार की गई सूची से ठीक से बाहर रखा गया है या नहीं। आयोग की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में यह स्वीकार किया गया है कि आयोग ने अनारक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए नियमों के नियम 15 (ए) के तहत योग्यता अंकों के रूप में 38 प्रतिशत निर्धारित किए थे। अर्हता अंकों के रूप में 38 प्रतिशत निर्धारित करने के बाद, आयोग के लिए लिखित परीक्षा में 38.8 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के नाम को बाहर करना संभव नहीं था क्योंकि उच्च न्यायालय ने पहले सिफारिश की थी कि आयोग द्वारा परामर्श किए जाने पर 40 प्रतिशत अंक योग्यता अंक होने चाहिए। जवाबी हलफनामे में आयोग द्वारा योग्यता अंकों के रूप में 38 प्रतिशत अंक निर्धारित करने का निर्णय लेने के बाद योग्यता अंकों के किसी भी नए निर्धारण का कोई संदर्भ नहीं है। 19वीं प्रतियोगी न्यायिक सेवा परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के संबंध में। जब तक इस तरह का नया निर्धारण नहीं किया जाता है, तब तक लिखित परीक्षा में 38 प्रतिशत और

उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को मौखिक परीक्षा में उपस्थित होने और लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता के क्रम में नियमों के नियम 19 के तहत तैयार की गई सूची में शामिल होने का अधिकार होगा। उच्च न्यायालय ने यह ठहराते हुए त्रुटियां की कि आयोग ने योग्यता अंक 40 प्रतिशत केवल इसलिए निर्धारित किए थे क्योंकि उसने नियम 19 के तहत तैयार सूची में 40 प्रतिशत से कम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले किसी भी उम्मीदवार के नाम शामिल नहीं किए थे। इस तरह का गैर-समावेशन अपने आप में और अधिक के बिना आयोग द्वारा किए गए निर्णय के बराबर नहीं है। आयोग ने वास्तव में यह दलील नहीं दी कि उसने कोई नया निर्णय लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उच्च न्यायालय द्वारा आयोग की कार्रवाई का समर्थन करने के लिए बनाया गया एक नया मामला है जो योग्यता अंक 38 प्रतिशत तय करने के अपने फैसले के विपरीत था।

उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की स्वीकृति करने से एक ही परीक्षा के संबंध में अलग-अलग चरणों में दो अलग-अलग चरणों के दो अलग-अलग योग्यता अंक निर्धारित करने के विसंगति पूर्ण परिणाम भी सामने आएंगे। यानी एक उसी परीक्षा में उपस्थित हाने वाले 83 उम्मीदवारों के पहले बंच के लिए जिनका 16 सितंबर 1982 को नियुक्त किया गया था, इससे पहले कि नियुक्तियों के बारे में कोई विवाद उत्पन्न हुआ था और दूसरा 38 उम्मीदवारों के अगले बंच के लिए जिनके नाम फैसले के बाद राज्यपाल को भेजी गए थे। रिट याचिकाओं में सी.डब्लू.जे.सी 1983 का सं. 1868 और सी.डब्लू.जे.सी सं. 1983 का 2209। इस असंगति को अस्तित्व में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसा हो सकता है कि वास्तव में 83 उम्मीदवारों के पहले बंच में से कोई भी अनारक्षित वर्ग का उम्मीदवार नहीं था जिसने लिखित प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हो, लेकिन जो बात प्रासंगिक है वह मानक है जो उक्त सूची जारी करते समय लागू किया गया था। तैयार सूची बिना किसी संदेह के उपयोग द्वारा अनारक्षित वर्ग के लिए 38 प्रतिशत

निर्धारित अर्हता अंकों के आलोक में तैयार की गई होगी जिसके आधार पर अपीलार्थी सहित दोनों बैचों से संबंधित सभी उम्मीदवारों का मौखिक परीक्षण आयोजित किया गया था। जब अगली सूची तैयार की गई तो उस मानक को बदला नहीं जा सका। उच्च न्यायालय मामले के इस पहलू की सराहना करने में विफल रहा है।

हमारे सामने मौजूद सामग्री को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि आयोग ने 38 प्रतिशत योग्यता अंक के रूप में निर्धारित किया था अनारक्षित श्रेणी के लिए योग्यता अंक और बाद में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। मान लीजिए कि जिन दो उम्मीदवारों के नाम क्रम संख्या 36 और 37 के विरुद्ध दिखाए गए हैं, उन्होंने कुल 415 अंक प्राप्त किए थे और क्रम संख्या 38 के विरुद्ध दिखाए गए उम्मीदवार ने 413 अंक प्राप्त किए थे जबकि अपीलार्थी ने 416 अंक प्राप्त किए थे। इसलिए, अपीलार्थी का नाम आयोग द्वारा नियम 19 के तहत सरकार को सौंपी गई सूची में क्रम संख्या 36 में उम्मीदवार के नाम के ऊपर रखा जाना चाहिए था। ऐसा न करके आयोग ने नियमों और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का भी उल्लंघन किया था।

इसलिए, उच्च न्यायालय के निर्णयों को दरकिनार किया जाना चाहिए और हम तदनुसार इसे दरकिनार कर देते हैं। हम आयोग को निर्देश देते हैं कि वह सरकार को एक संशोधित सूची प्रस्तुत करे जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 36 के ऊपर दिखाया गया है और हम राज्य सरकार को आगे निर्देश देते हैं कि वह नियम 19 के तहत मुन्सिफ के रूप में नियुक्ति के लिए अपीलार्थी के मामले पर विचार करे जैसे कि उसका नाम उस उम्मीदवार के ऊपर दिखाया गया हो जिसका नाम क्रम संख्या 1 के सामने दिखाया गया है। उसकी नियुक्ति पर, अपीलार्थी को वरिष्ठता सूची में अनुक्रमांक 36 के सामने दिखाए गए उम्मीदवार के ऊपर रखा जाएगा और उसे सभी वेतनवृद्धि आदि दिए जाएंगे जैसे कि वह

उस तारीख को नियुक्त किया गया था जिस दिन अनुक्रमांक 36 पर उम्मीदवार की नियुक्ति की गई थी।

तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। उत्तरदाता 1 और 2 को उपरोक्त का एक महीने के भीतर निर्देश पालन करने का निर्देश दिया गया है। अपीलार्थी उन लागतों का हकदार है जो हम 3,000/- रुपये में निर्धारित करते हैं।

एम.एल.ए